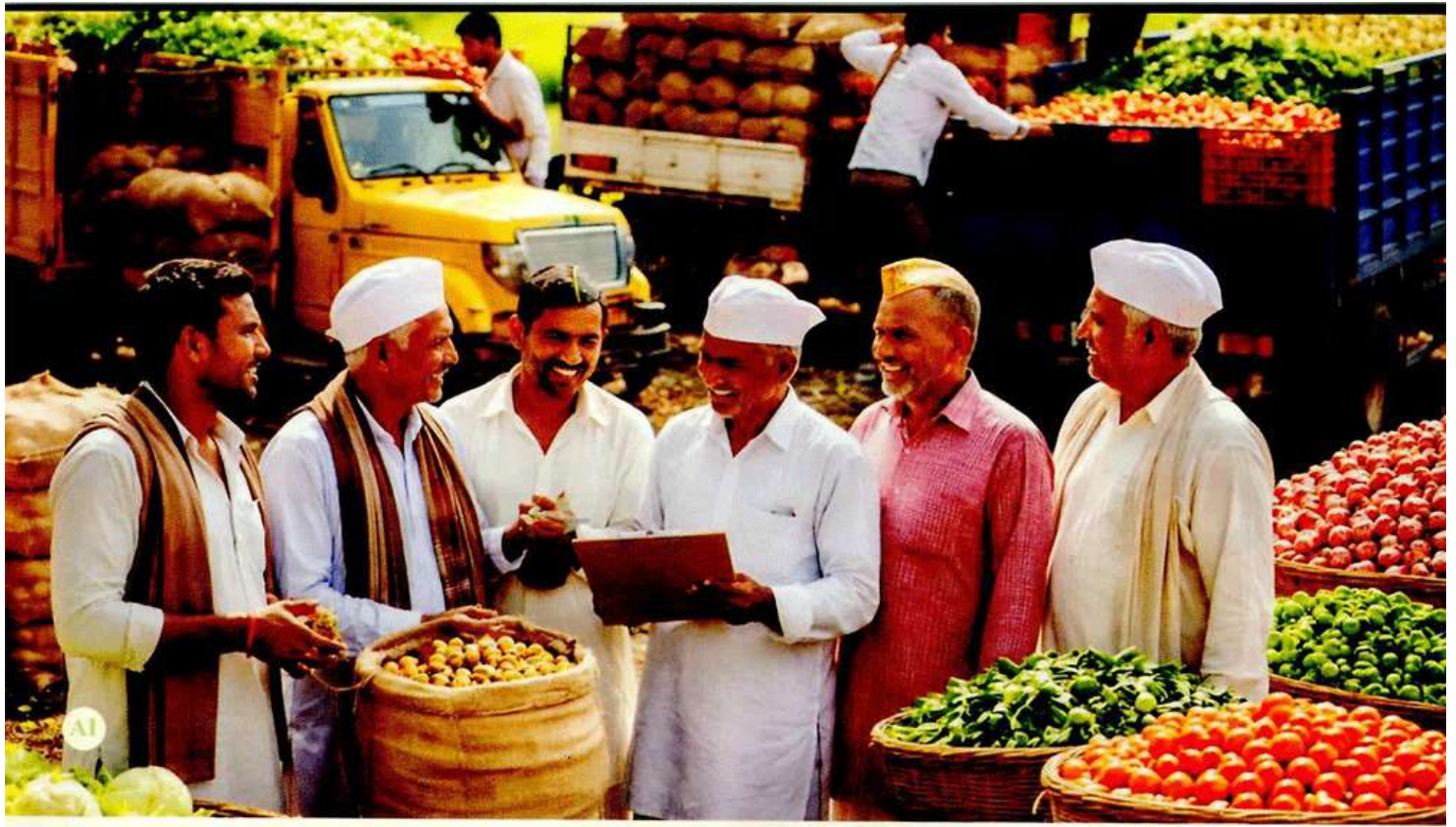




## सहकारिता और सामुदायिक भागीदारी

डॉ. भरत सिंह  
डॉ. दिव्या भयाल

विकसित भारत@2047 की दिशा में ग्रामीण विकास को केवल कृषि उत्पादकता तक सीमित न रखकर गाँवों की अर्थव्यवस्था को सशक्त करना आवश्यक है। यह लेख मृदा स्वास्थ्य, सामूहिक प्रयास और स्थानीय मूल्य सृजन को बेहतर आजीविका से जोड़ने वाले समुदाय-आधारित दृष्टिकोण पर केंद्रित है। सहकारी समितियाँ, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और अन्य सामुदायिक संस्थाएँ सामूहिक खरीद, उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के ज़रिए किसानों को बेहतर मूल्य और आय दिला सकती हैं। साथ ही, मृदा परीक्षण, जैविक आदान, डिजिटल कृषि और ग्राम-स्तरीय उद्यमों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है।

वि

कसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का समृद्ध, सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है। कृषि आज भी ग्रामीण आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका का मुख्य आधार है, लेकिन लघु और सीमांत किसानों को कृषि आदानों की बढ़ती लागत, छोटी और बिखरी जोतों, बाज़ार तक सीमित पहुँच तथा मृदा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से अनेक समस्याओं का समाधान केवल व्यक्तिगत स्तर पर किए गए प्रयासों से संभव नहीं है। सहकारी समितियाँ, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता

समूह (एसएचजी) और अन्य सामुदायिक संगठन संसाधनों, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के साझा उपयोग तथा सामूहिक रूप से बाज़ार तक पहुँच बनाने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान कर सकते हैं। यदि किसान, महिलाएँ, युवा और स्थानीय संस्थाएँ मृदा, जल, उत्पादन और मूल्य शृंखला से जुड़े प्रयासों में सामूहिक रूप से योगदान दें तो गाँवों में रोज़गार, आय और ग्रामीण उद्यमिता के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। इस प्रकार, सामूहिक प्रयासों पर आधारित सतत विकास गाँवों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है और विकसित भारत के व्यापक लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

लेखक डीन तथा सह-लेखक संविदा शिक्षक, आरवीएसकेवीवी कृषि महाविद्यालय, इंदौर हैं। ईमेल: singhbharat05@gmail.com

## व्यक्तिगत पहल से साझा प्रयास की ओर

भारत में लघु और सीमांत किसानों को अक्सर उचित लागत पर गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री, मशीनरी, भंडारण सुविधाएँ, वित्तीय सहायता और उपयुक्त बाजार उपलब्ध होने में कठिनाई होती है। जब प्रत्येक किसान को इन संसाधनों की व्यवस्था अलग-अलग करनी पड़ती है तो खेती की लागत बढ़ सकती है और बाजार में मोलभाव करने की उसकी क्षमता सीमित रह सकती है। सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सामुदायिक समूहों के माध्यम से मिलकर कार्य करने से इन कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिल सकती है। किसान अपनी जरूरतों के अनुसार सामूहिक रूप से बीज, उर्वरक, मशीनरी और अन्य कृषि सामग्री बड़ी मात्रा में बेहतर कीमतों पर खरीद सकते हैं। साथ ही, कृषि मशीनरी के साझा उपयोग और सामुदायिक स्तर पर मशीनरी उपलब्ध कराने की व्यवस्था से प्रत्येक किसान को अलग से भारी निवेश करने की आवश्यकता भी कम हो सकती है।

सामूहिक उत्पादन योजना से तकनीकी मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री और संस्थागत सहयोग तक किसानों की पहुँच बेहतर हो सकती है। सामूहिक विपणन भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे किसानों की मोलभाव करने की क्षमता बढ़ सकती है, बिचौलियों पर निर्भरता कम हो सकती है और उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने के अवसर बढ़ सकते हैं। किसान समूह ग्रेडिंग, भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मूल्य संवर्धन जैसे कार्य भी सामूहिक रूप से कर सकते हैं। इस प्रकार, व्यक्तिगत प्रयासों से आगे बढ़कर संगठित सामूहिक प्रयासों को अपनाया केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं है बल्कि इससे उत्पादन लागत कम करने, किसानों की आय बढ़ाने, गाँव स्तर पर उद्यमों को प्रोत्साहित

करने और अधिक सुदृढ़ तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

## मृदा स्वास्थ्य: समुदाय की साझा संपदा

खेत की मिट्टी भले ही अलग-अलग किसानों के स्वामित्व में हो, लेकिन मृदा पूरे गाँव के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। उसकी गुणवत्ता का सीधा प्रभाव कृषि उत्पादकता और गाँव की दीर्घकालिक समृद्धि पर पड़ता है। इसलिए मृदा स्वास्थ्य को किसान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ-साथ समुदाय की साझा जिम्मेदारी के रूप में भी देखा जा सकता है। ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य मानचित्रण से किसानों को मिट्टी में पोषक तत्वों की वास्तविक आवश्यकता का पता लगाने और उसी के अनुसार उर्वरकों के उपयोग में मदद मिल सकती है। जैविक पदार्थों के उपयोग, संतुलित उर्वरीकरण, जैव उर्वरकों, फसल अवशेषों के पुनर्चक्रण और उपयुक्त फसल चक्र को सामूहिक रूप से बढ़ावा देने से मृदा की गुणवत्ता और पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता में सुधार किया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन और प्रशिक्षित ग्रामीण युवा मृदा परीक्षण, कम्पोस्ट निर्माण, जैविक कृषि सामग्री के उत्पादन और इससे जुड़ी कृषि सेवाओं का कार्य कर सकते हैं। ये गतिविधियाँ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने और छोटे ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने में भी सहायक हो सकती हैं। बेहतर मृदा स्वास्थ्य अनावश्यक कृषि खर्च को कम करने के साथ-साथ फसल उत्पादकता बढ़ाने में भी काफी सहायक सिद्ध होता है और किसानों की आय में सुधार लाने में मदद करता है। साथ ही, यह सतत कृषि को भी बढ़ावा देता है। इस प्रकार, स्वस्थ मृदा उत्पादक खेतों और समृद्ध गाँवों की आधारशिला बन सकती

है तथा विकसित भारत की व्यापक परिकल्पना में सार्थक योगदान दे सकती है।

## सामूहिक खेती से सामूहिक मूल्य सृजन

किसानों का आपसी सहयोग केवल कृषि सामग्री की सामूहिक खरीद या उत्पादन की संयुक्त योजना तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि इसमें भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन को भी शामिल किया जाना चाहिए। छोटे और सीमांत किसान जब अपनी उपज अलग-अलग और फसल कटाई के तुरंत बाद बेचते हैं तो कई बार उन्हें उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), सहकारी संस्थाएँ और सामुदायिक उद्यम किसानों को उपज की सामूहिक रूप से ग्रेडिंग, भंडारण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग करने तथा उसके बाद उसे बाजार तक पहुँचाने में मदद कर सकते हैं।

सोयाबीन, दलहन, गेहूँ, मोटे अनाज और स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण अन्य फसलों के लिए

# मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन

→ प्रमुख उपलब्धियाँ ←



**लगभग 26 करोड़**

मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए

पोषक तत्वों पर आधारित, फसल-विशिष्ट उर्वरक सिफारिशों के साथ किसानों को सशक्त बनाना



**7.2 लाख**

प्रदर्शन आयोजित किए गए

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना



**70,002**

कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया गया

मृदा स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं की मजबूती और घर-घर पहुँच सुनिश्चित करना

गाँवों में प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। इससे खेत के आसपास ही रोजगार और आय के अतिरिक्त अवसर पैदा हो सकते हैं। इस प्रकार का मूल्य संवर्धन, बाजार तक किसानों की पहुँच बेहतर कर सकता है, उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिला सकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है।

### ग्रामीण परिवर्तन के प्रेरक: महिलाएँ और युवा

ग्रामीण परिवर्तन को सार्थक और स्थायी बनाने में महिलाओं और ग्रामीण युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बीज उत्पादन, कम्पोस्ट और जैविक कृषि सामग्री तैयार करने, खाद्य प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन तथा स्थानीय विपणन जैसी गतिविधियाँ अपना सकते हैं। शिक्षित ग्रामीण युवा मृदा परीक्षण, कृषि मशीनरी सेवाओं, डिजिटल कृषि, मौसम संबंधी जानकारी और बाजार की नवीनतम सूचनाओं के माध्यम से किसानों की सहायता कर सकते हैं। कृषि मूल्य श्रृंखला में महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ने पर गाँव धीरे-धीरे केवल कच्चे माल के उत्पादन तक सीमित न रहकर कौशल, उद्यमिता और नवाचार के केंद्र के रूप में विकसित होने लगते हैं। इस प्रकार की सामुदायिक भागीदारी स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करती है, पलायन की आवश्यकता कम करती है, परिवारों की आय को मजबूती देती है और कृषि को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में अधिक सक्षम बनाती है।

### डिजिटल कृषि: ज्ञान और बाजार से किसानों का जुड़ाव

डिजिटल साधन किसानों को वैज्ञानिक जानकारी, कृषि सेवाओं और बाजार से अधिक आसानी से जोड़ते हैं। गाँव स्तर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म मौसम, मृदा स्वास्थ्य, फसल प्रबंधन, कीट एवं रोग संबंधी समस्याओं, सरकारी योजनाओं और बाजार भाव की नवीनतम जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। ग्रामीण युवा स्थानीय डिजिटल कृषि सहायक के रूप में काम करते हुए छोटे और सीमांत किसानों को इन सेवाओं का उपयोग कर बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और किसान समूह भी कृषि सामग्री की सामूहिक खरीद, उपज के सामूहिक संग्रह, ऑनलाइन विपणन और खरीदारों से सीधे संपर्क के लिए डिजिटल प्रणालियों का उपयोग कर सकते हैं। समय पर और आसानी से जानकारी मिलने से अनिश्चितता कम होती है, कृषि संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलती है।

### मृदा से आजीविका

मृदा स्वास्थ्य में सुधार का लाभ केवल फसल की बेहतर पैदावार तक सीमित नहीं रहता; इससे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय और अतिरिक्त आय के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। किसान और सामुदायिक समूह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैव सामग्री, फसल अवशेषों तथा पशु अपशिष्ट से कम्पोस्ट, वर्मीकम्पोस्ट और

अन्य जैविक कृषि सामग्री तैयार कर सकते हैं। इससे बाहर से खरीदी जाने वाली महँगी कृषि सामग्रियों पर निर्भरता कम होगी और मृदा में जैविक पदार्थ का स्तर बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। ग्राम उद्यम मृदा परीक्षण, जैव-उत्पादों के निर्माण, कम्पोस्ट तैयार करने और पोषक तत्वों के प्रबंधन संबंधी परामर्श जैसी सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) मिलकर इन उत्पादों का निर्माण, पैकेजिंग और विपणन कर सकते हैं, जिससे गाँव में ही रोजगार और आय के अवसर पैदा होंगे। यह व्यवस्था ऐसी चक्रीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है, जिसमें खेतों से निकलने वाले अवशेषों को उपयोगी संसाधनों में बदला जाता है।

### निष्कर्ष

विकसित भारत@2047 का लक्ष्य तभी साकार होगा, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी और इसे संबल देने वाले किसानों के लिए आगे बढ़ने के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। स्वस्थ मृदा इस परिवर्तन की नींव बन सकती है, लेकिन इसके लिए खेतों तक सीमित व्यक्तिगत प्रयासों से आगे बढ़कर संगठित सामुदायिक प्रयासों की ओर कदम बढ़ाना होगा। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से किसान मृदा एवं जल प्रबंधन से लेकर कृषि सामग्री, प्रौद्योगिकी, उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन तक हर स्तर पर मिलकर कार्य कर सकते हैं।

इस सामूहिक प्रयास से कृषि सामग्री पर होने वाला खर्च घटेगा, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, मोलभाव की क्षमता बढ़ेगी और किसानों को अपनी उपज का अधिक मूल्य मिल सकेगा। महिलाएँ और ग्रामीण युवा भी मृदा परीक्षण, जैव-उत्पादों के निर्माण, मूल्य संवर्धन, डिजिटल सेवाओं तथा ग्राम उद्यमों के माध्यम से इस प्रयास के महत्वपूर्ण भागीदार बन सकते हैं, जिससे उनके लिए रोजगार और आय की नई राहें खुलेंगी। सामुदायिक स्तर पर मृदा और जल का प्रबंधन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की क्षमता को और मजबूत कर सकता है तथा भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायक हो सकता है।

अतः लक्ष्य केवल फसल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि ऐसे समृद्ध गाँव का निर्माण करना है, जहाँ किसान उद्यमी बन सकें, महिलाएँ आर्थिक क्षेत्र में अधिक सशक्त भूमिका निभाएँ, युवा ग्रामीण नवाचार को आगे बढ़ाएँ और मृदा की उत्पादकता लंबे समय तक बनी रहे। ये सभी प्रयास मिलकर समुदायों को मजबूत बना सकते हैं, स्थानीय स्तर पर मूल्य सृजन कर सकते हैं और किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। इससे चुनौतियों का सामना करने में सक्षम और समावेशी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। □

